वर्ष : 03- अंक : 26 - मई 2025

International Year of Cooperatives 2025

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

हर गांव तक सहकारी डेयरी का विस्तार

डेयरी क्षेत्र की वित्तीय जरुरतें पूरी करेगा एनसीडीसी 11

नया भारत 'विकास के साथ विरासत' के मंत्र से कर रहा तेज प्रगति 22

अनुक्रमणिका

International Year of Cooperatives 2025

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार उदय

मई 2025, अंक 26, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
संतोष कुमार शुक्ला

संपादक
रोहित कुमार

सह संपादक
अँक अँजलीदीप

सदस्य
माधवी एम. विप्रदास
विवेक सक्सेना
हितेंद्र प्रताप सिंह
राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

sahkaruday@iffco.in

महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

इफको से जुड़ने के अन्य पते:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

हर गांव तक सहकारी डेयरी का विस्तार

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से श्वेत क्रांति-2.0 को सफल बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पशुपालकों, दूध उत्पादकों, छोटे व भूमिहीन किसानों की वित्तीय हालत में सुधार के साथ रोजगार के अवसर सृजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

आवरण कथा

पेज 06 देखें

पेज 14 देखें

काशी भारत की विविधता का प्रतिनिधि

काशी ने आधुनिकता को अपनाते हुए न सिर्फ अपनी विरासत को संजोया है बल्कि उज्ज्वल भविष्य को भी अपनाया है। भगवान महादेव द्वारा निर्देशित प्राचीन काशी अब प्रगतिशील और पूर्वांचल के आर्थिक मानचित्र का केंद्र भी है।

पेज 26 देखें

'हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में यात्रा करने का सपना पूरा'

पेज 28 देखें

सहकारी समितियों की होगी ऑनलाइन ऑडिटिंग

पेज 29 देखें

पशुपालन बन रहा ग्रामीण समृद्धि का आधारः भूटानी

पेज 17 देखें

सामाजिक समरसता व सांस्कृतिक जागरण के संकल्प को पूरा कर रही मोदी सरकार

देश में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरण बढ़ाने का जो संकल्प बाबा बालनाथ महाराज ने लिया था, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारें पूरा कर रही हैं।

पेज 18 देखें

देश के निर्माण में गुजराती साहित्य के पत्र-पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

पेज 20 देखें

भारत ने एकाधिकार नहीं, मानवता को प्राथमिकता दी

पेज 24 देखें

भारतीय संस्कृति की राजदूत बनकर ब्रह्माकुमारी संस्था विश्व में दे रही शांति का संदेश

सहकारी डेयरियों के विस्तार से सशक्त होंगे गांव

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है जहां पशुपालन ग्रामीण जीवन एवं अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन ग्रामीण परिवारों की आय के एक सशक्त स्रोत के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में सहकारी डेयरी संस्थाओं ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है, जिससे न केवल दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं तक शुद्ध और सुलभ दूध की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित हो रही है।

सहकारी डेयरी एक ऐसी संस्था है जो किसानों व पशुपालकों द्वारा संचालित होती है, जहां वे मिलकर दूध का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवतापूर्ण आपूर्ति के साथ- साथ अपने सदस्यों को अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। भारत में सहकारी डेयरी का सबसे सशक्त उदाहरण 'अमूल' है, जिसने 'श्वेत क्रांति' को जन्म दिया और भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। आज भारत 23.9 करोड़ टन से अधिक दूध उत्पादन करता है।

देश में सहकारी डेयरी प्रणाली तीनस्तरीय संरचना पर आधारित है। गांव स्तर की दुग्ध उत्पादक समितियां, जिला स्तर के दूध संघ और राज्य स्तर के महासंघ। डेयरी क्षेत्र न केवल पोषण और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक सशक्त माध्यम है। लाखों ग्रामीण परिवार डेयरी फार्मिंग पर अपनी आय के मुख्य सहायक स्रोत के रूप में निर्भर हैं। विशेष रूप से सीमांत किसान और महिलाएं इससे सीधे लाभान्वित होती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है।

मोदी सरकार का 'हर गांव तक सहकारी डेयरी का विस्तार' एक ऐसा प्रयास है जो ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। वर्ष 2025 के अंत तक सहकारी डेयरी क्षेत्र को और विस्तार देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और 'श्वेत क्रांति 2.0' प्रमुख हैं। मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य दूध की खरीद, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण को बेहतर बनाना, किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच दिलाना, मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक लाभ सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त करना है।

निःसंदेह संशोधित डेयरी विकास कार्यक्रम आधुनिक बुनियादी ढांचे, नई तकनीकों और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से नवगठित सहकारी दुग्ध समितियों को सहयोग प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण रोजगार सृजन में सहायक होगा, बल्कि देश भर के किसानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा।

'सहकार उदय' पत्रिका का यह अंक 'सहकारी डेयरी विस्तार' विषय पर केंद्रित है। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण आलेखों के साथ अन्य उपयोगी और ज्ञानवर्धक लेखों को भी सम्मिलित किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अंक आपके लिए लाभकारी और प्रेरणादायक सिद्ध होगा। ■

सादर धन्यवाद

जय सहकार

सहकार उवाच

'विकास भी-विरासत भी' के मंत्र के साथ नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की यात्रा में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति केवल हमारी पहचान से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि यह हमारे सामर्थ्य को भी बढ़ाती है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गन्ना किसानों को मोदी सरकार का उपहार। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए गन्ने का एफआरपी ₹355 प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवारों के साथ-साथ चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। गन्ना उत्पादकों की समृद्धि और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध मोदी जी का यह निर्णय किसानों के जीवन को और अधिक बेहतर और सुगम बनाएगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सीसीपीए की बैठक ने आगामी जनगणना में जाति आधारित जानकारी को शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला देश में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करेगा और हर क्षेत्र के विकास को दिशा देगा। मोदी सरकार द्वारा उठाया गया निर्णायक कदम समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को न्याय देगा, उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और एक समावेशी भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा।

श्री मुरलीधर मोहोल,
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकारी वस्तु एवं आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से सहकारी आर्थिक ढांचे की सफलता और समृद्धि के लिए उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और मार्केटिंग की सुदृढ़ व्यवस्था देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इनके लिए संबंधित क्षेत्र में मदद, प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट के रूप में व्यवस्था होनी जरूरी है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

बीज, ऑर्गेनिक और एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को अब अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। विश्व के बाजार में किसान को जाने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इससे होने वाला मुनाफा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो रहा है। यह मुनाफा अब किसानों को मिल रहा है, किसी व्यापारी को नहीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इफको

भारत सरकार ₹516 करोड़ रुपए की लागत से देश की सभी पैक्स का कम्प्यूटरीकरण कर रही है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में जम्मू कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व झारखंड अग्रणी चल रहे हैं। आज देश के कई राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक कम्प्यूटर नेटवर्क के कारण नाबार्ड से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था से सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आई है।

सहकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का एफआरपी 15 रुपए बढ़ा

पांच करोड़ किसानों को मिली बड़ी सौगात

सहकार उदय टीम

मोदी सरकार ने देश के 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 15 रुपए की वृद्धि करने का फैसला किया गया है। 1 अक्टूबर, 2025 से होने वाले गन्ने की खरीद के लिए चीनी मिलें अब किसानों को 355 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देंगी जो अभी 340 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में कीमतें अलग-अलग होती हैं क्योंकि राज्य सरकारें भी किसानों के हित में एसएपी (राज्य परामर्श मूल्य) देने की घोषणा करती हैं जो एफआरपी से अधिक होता है। इसके अलावा, एक अन्य फैसले में सरकार ने खांडसारी इकाइयों के लिए गन्ना किसानों को एफआरपी देना अनिवार्य कर दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पेराई सीजन 2025-26 के लिए गन्ना का एफआरपी 15 रुपए बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। यह एफआरपी 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी दर के आधार पर तय किया गया है। इससे अधिक रिकवरी होने पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए किसानों को 3.46 रुपए प्रति क्विंटल भाव अलग से दिया जाएगा, जबकि रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती होगी। जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है उनके लिए कीमतों में कटौती नहीं होगी और किसानों को गन्ने का एफआरपी 329.05 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। एफआरपी का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया जाता है।

एफआरपी में वृद्धि

वर्ष	एफआरपी	वृद्धि
2020-21	285	10
2021-22	290	05
2022-23	305	15
2023-24	315	10
2024-25	340	25
2025-26	355	15

(एफआरपी और वृद्धि रुपए में)

➲ 340 रुपए से बढ़कर 355 रुपए प्रति क्विंटल हुआ गन्ने का एफआरपी, खांडसारी इकाइयों के लिए भी एफआरपी देना हुआ अनिवार्य

एफआरपी देंगी खांडसारी इकाइयां

एक अन्य फैसले में केंद्र सरकार ने छह दशक पुराने शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1966 में संशोधन कर खांडसारी चीनी और खांडसारी इकाइयों को नियमन के दायरे में लाने का फैसला किया है। अब प्रतिदिन 500 टन या इससे ज्यादा पेराई क्षमता (टीसीडी) वाली खांडसारी इकाइयों को भी चीनी मिलों की तरह गन्ना किसानों को एफआरपी देना पड़ेगा। भारत सरकार ने शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 1966 की व्यापक समीक्षा के बाद शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 तैयार किया है। इसका उद्देश्य उद्योग में बदलाव और तकनीकी प्रगति के अनुरूप चीनी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामकीय ढांचे को सरल और सुव्यवस्थित करना है। इससे खांडसारी इकाइयों द्वारा किसानों को एफआरपी का भुगतान सुनिश्चित होगा और चीनी उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।

खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 373 खांडसारी इकाइयां लगभग 95,000 टीसीडी की कुल क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इनमें से 66 खांडसारी इकाइयां 500 टीसीडी से अधिक क्षमता की हैं जिनकी कुल क्षमता लगभग 55200 टीसीडी। ऐसी इकाइयों द्वारा पर्याप्त मात्रा में खांडसारी चीनी का उत्पादन किया जा रहा है। इन्हें अब शुगर कंट्रोल ऑर्डर के तहत रेगुलेट किया जाएगा। इन इकाइयों को चीनी उत्पादन का डेटा सरकार के साथ डिजिटली साझा करना होगा। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, प्रणालियों के एकीकरण से कार्यकुशलता बढ़ेगी और रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा।

देश के 5 करोड़ से ज्यादा किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा श्रमिक चीनी मिलों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। इसके अलावा, लाखों लोग मजदूरी और परिवहन सहित गन्ना की विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत हैं। सरकार के इन फैसलों का फायदा इन सभी को मिलेगा।■

International Year 2025 of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

हर गांव तक सहकारी डेयरी का विस्तार

सहकार उदय टीम

- कोऑपरेटिव डेयरी की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का लक्ष्य
- पांच वर्ष में सहकारी डेयरी की प्रतिदिन दूध की खरीद 660 लाख किलो से बढ़ाकर 1,007 लाख किलोग्राम करने का लक्ष्य

सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से श्वेत क्रांति-2.0 को सफल बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पशुपालकों, दूध उत्पादकों, छोटे व भूमिहीन किसानों की वित्तीय हालत में सुधार के साथ रोजगार के अवसर सृजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दुग्ध उत्पादन, संकलन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया गया है। दूसरी श्वेत क्रांति को सफल बनाने के लिए इससे जुड़े विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इसके लिए देश में एक लाख से अधिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के गठन का फैसला किया गया है, ताकि हर गांव तक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहुंच हो जाए।

ग्राम स्तर पर दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापित करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए नए हाइटेक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे दुग्ध संकलन और दुग्ध विक्रय में वृद्धि हो सकेगी। दूध

परियोजना के लाभ

दूध संकलन, परीक्षण, चिलिंग, लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण का ढांचा होगा मजबूत

इन कदमों से डेयरी मूल्य श्रृंखला को मिलेगी मजबूती

छोटे डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्राप्त होगी, उचित एवं लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा

प्राथमिक डेयरी सोसाइटियों के नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद

डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी

श्वेत क्रांति 2.0 आजीविका से जुड़ी

2030 तक कुल दूध उत्पादन 23 करोड़ टन से बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य

- श्वेत क्रांति 2.0 से डेयरी क्षेत्र में दूध का संकलन बढ़कर हो जाएगा डेढ़ गुना
- देश के डेयरी से जुड़े सभी परिवारों को सहकारिता से जोड़ना प्रमुख उद्देश्य
- श्वेत क्रांति 2.0 के दौरान लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतें पैक्स से जुड़ेंगी
- एक लाख डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की योजना

> श्वेत क्रांति 2.0 महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण का काम करेगा। दूध के उत्पादन और खास कर सहकारी डेयरियों के साथ माताएं-बहनें जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम डेयरी क्षेत्र जितना कोई और नहीं कर सकता। कई राज्यों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। गुजरात में 36 लाख बहनें डेयरी क्षेत्र से जुड़कर 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती हैं। अमूल पूरे विश्व में खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन गया है।
>
> **- श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

की घरेलू मांग के साथ वैश्विक बाजार में दुग्ध उत्पादों की पैठ को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की गई है। मल्टी डेयरी पैक्स (एमपैक्स) को वित्तीय मदद के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) ने हाथ बढ़ाए हैं। देश की तकरीबन 10,000 एमपैक्स को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक सोसाइटी को न्यूनतम 40 हजार रुपए की मदद दी जाएगी।

श्वेत क्रांति 2.0 से दूध संकलन, परीक्षण, चिलिंग, लॉजिस्टिक और प्रसंस्करण का ढांचा मजबूत किया जाएगा जिससे डेयरी मूल्य श्रृंखला सशक्त होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए इसे बूस्टर डोज माना जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय की पहल से पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के माध्यम से देश के कुल दूध उत्पादन में डेयरी कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी को आगामी पांच वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन 23.9 करोड़ टन से अधिक हो गया है। 2023 तक इसे बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया गया है। दुग्ध के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24.64 प्रतिशत हो गई है। लेकिन इसमें सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी सिर्फ 14 प्रतिशत ही है। इसे बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 22 प्रतिशत करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नोडल भूमिका निभाएगा। योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक पशुपालकों को डेयरी कोऑपरेटिव से जोड़ा जाएगा। ■

गोबर 'धन' से मालामाल होंगे किसान

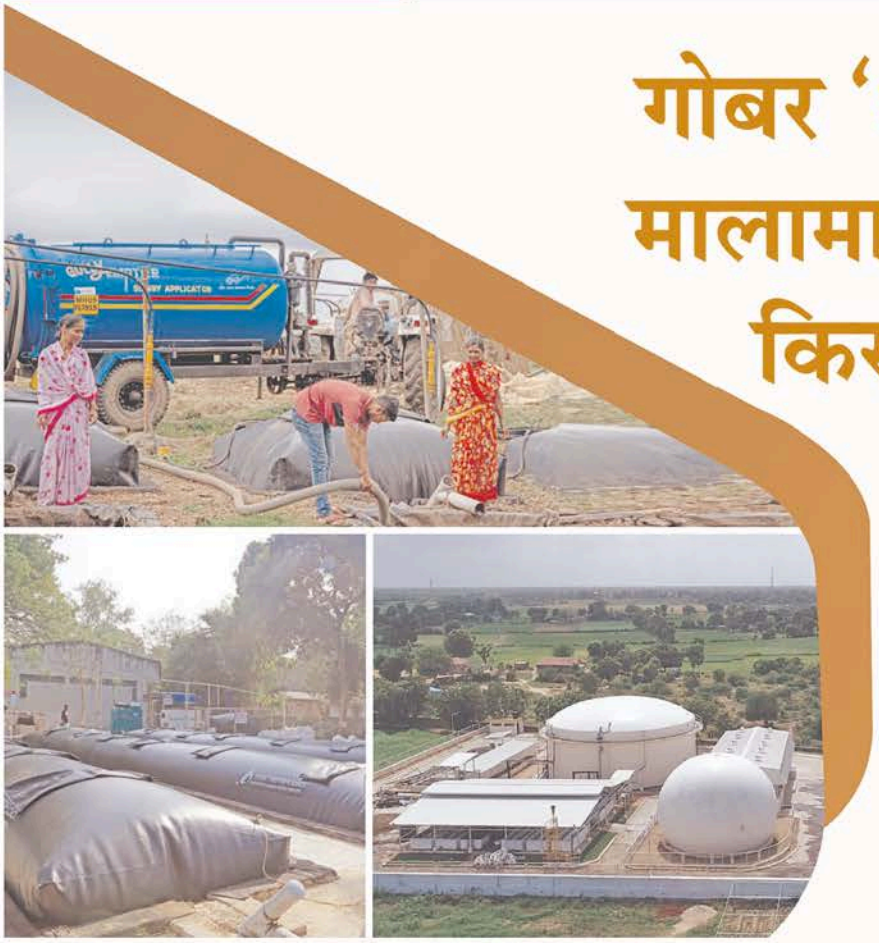

- एनडीडीबी ने देश भर में बायोगैस प्लांट का विस्तार करने के लिए एमओयू किया
- गोबर से कमाई और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बनाई योजना

सहकार उदय टीम

श्वेत क्रांति-2 के माध्यम से सहकारी डेयरी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई-नई योजनाओं पर काम रही है। दूध उत्पादन के साथ गाय और भैंसों के गोबर से सहकारी क्षेत्र के डेयरी संचालकों और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इस बाबत वित्तीय मदद मुहैया कराएगा। एनडीडीबी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिसका अब देशव्यापी विस्तार किया जाएगा।

> गांवों से पलायन रोकने और भूमिहीन एवं छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण विकल्प है। श्वेत क्रांति-2 का मुख्य लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी है।
>
> **- श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

नई दिल्ली में मार्च में आयोजित ''डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला'' में 15 राज्यों के 26 दुग्ध संघों ने देशभर में बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने मसौदा पेश किया था। इन संघों से एनडीडीबी ने बायोगैस प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया है।

दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर एक है और विश्व की डेयरी कहलाता है। डेयरी क्षेत्र कृषि जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडिशन) में 30 प्रतिशत योगदान देता है। गांवों से पलायन रोकने और भूमिहीन एवं छोटे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण विकल्प है। न सिर्फ दूध उत्पादन, बल्कि गोबर से कमाई और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी देशभर में बायोगैस उत्पादन को विस्तार देने की योजना पर काम कर रहा है। देश में 53 करोड़ से

अधिक पशुधन हैं जिनमें से लगभग 30 करोड़ गाय और भैंस हैं। इसलिए बड़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध है जिसका उपयोग जैविक खाद, जैव ईंधन आदि के लिए किया जा सकता है। एनडीडीबी ने लघु और बड़े पैमाने पर कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं और टिकाऊ डेयरी हस्तक्षेपों के वित्त पोषण के लिए एनडीडीबी सस्टेन प्लस परियोजना के तहत वित्त पोषण पहलों का शुभारंभ किया है। छोटे और बड़े बायोगैस संयंत्रों और कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनडीडीबी ने 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ नई वित्त पोषण योजना शुरू की है। इससे अगले 10 वर्षों में विभिन्न खाद प्रबंधन मॉडलों को बढ़ाने में सुविधा होगी जिससे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। इन पहलों से डेयरी फार्मिंग में चक्रीय प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाने, कुशल खाद प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने तथा पर्यावरणीय प्रभावों के कम होने की उम्मीद है।

जैविक खाद उत्पादन से आर्गेनिक खेती को मिलेगा बल

डेयरी क्षेत्र में चक्रीयता और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ ईंधन और जैविक खाद के उत्पादन के लिए गोबर का उपयोग किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। जैविक खाद के इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के प्रयासों से डेयरी क्षेत्र काफी हद तक असंगठित से संगठित क्षेत्र में बदल रहा है। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को नवाचार के साथ एकीकृत करने से न केवल हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाखों किसानों की समृद्धि भी सुनिश्चित होगी।

बायोगैस के प्रमुख मॉडल

जकारियापुरा मॉडलः गुजरात के आणंद जिले के बोरवद तालुका के जकारियापुरा गांव के तीन चौथाई से ज्यादा घरों में पशुपालन होता है जिनमें भैंसों की संख्या ज्यादा है। यहां के किसानों का मुख्य रोजगार दूध उत्पादन ही है। ये अमूल को अपना दूध बेचते हैं। पहले ये पशुपालक गोबर को इकट्ठा कर उनका इस्तेमाल खाद के रूप में अपने खेतों में करते थे। यह पारंपरिक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल देशभर के पशुपालक लंबे समय से करते रहे हैं। गोबर से कमाई करने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एनडीडीबी ने यहां 1.2 करोड़ रुपए की लागत से सभी पशुपालकों के घरों में 2 घनमीटर के गोबर गैस प्लांट (एक प्लांट की कीमत करीब 25 हजार रुपये) लगाए जिससे रोजाना करीब 24 हजार लीटर स्लरी (प्लांट से निकलने वाला तरल गोबर) निकलती है।

स्लरी का इस्तेमाल सीधे खेतों में भी किया जाता है और इससे जैविक खाद भी बनाई जाती है। बायोगैस प्लांट लगाने के बाद अमूल के जरिये उसकी खरीद और मूल्यवर्धित कर जैविक खाद बनाई जा रही है। इससे गांव के लोगों को अतिरिक्त आमदनी होने लगी। इसके साथ कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिला। इसके अलावा, प्लांट से पशुपालकों को मुफ्त में खाना पकाने के लिए बायोगैस मिलने लगा जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च बचने लगा। इससे गांव के किसानों की आमदनी तीन गुना तक बढ़ गई। आमतौर पर जो गाय-भैंस दूध नहीं देते हैं उन्हें पालना किसानों के लिए मुश्किल होता है लेकिन इस मॉडल के तहत अब ऐसे पशु भी आमदनी का जरिया बन गए हैं। इस सफल मॉडल का विस्तार अब पूरे देश में करने की तैयारी हो गई है जिसका फायदा किसानों को मिलेगा।

बनास मॉडल: गुजरात के बनासकांठा जिले की बनास डेयरी गोबर को बायोगैस और घोल (स्लरी) में बदल रही है। इसके बाद बायोगैस को शुद्ध करके बायो सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) और बायो सीएनजी (कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस) बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्लरी को कृषि क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए जैविक खाद में बदला जाता है जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होती है और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। कच्ची गैस को कम्प्रेस्ड किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए बनास डेयरी ने बायो सीएनजी पंप भी खोल रखा है।

वाराणसी मॉडल: इस मॉडल के तहत डेयरी के पास बड़े बायोगैस प्लांट लगाए गए। प्लांट से उत्पादित बाायोगैस का उपयोग डेरी प्लांट की थर्मल और ऊर्जा आवश्यकताओं कों पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर गोबर की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति आसपास के गौशालाओं और पशुपालकों से होती है। गोबर बेचना किसानों के लिए आमदनी का अतिरिक्त स्रोत बनता जा रहा है।

गोबर से कमाई करने वाले इन मॉडलों को देशभर में लागू करने के लिए ही एनडीडीबी ने दुग्ध संघों से एमओयू किया है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जैविक खाद का बड़ा बाजार तैयार करने में भी मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक, अगर यह योजना पूरे देश में लागू हो गई तो रोजगार के 22 लाख नए अवसर पैदा होंगे। बायोगैस उत्पादन के क्षेत्र के सफल प्रयोगों को 2 साल के लक्ष्य के साथ 250 जिला दुग्ध उत्पादक संघों में मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक लागू करने का कार्यक्रम बनाया जाएगा। साथ ही, जैविक खाद का शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए जिला स्तर के दुग्ध संघों और ग्रामीण डेयरियों के उन किसानों को सहकारिता से भी जोड़ने की कवायद की जाएगी जो अभी इससे नहीं जुड़े हैं। ■

एनडीडीबी के एमपीसीडीएफ से हाथ मिलाने के अवसर पर बोले श्री अमित शाह

सहकार उदय टीम

दुग्ध उत्पादन में सहकारी डेयरी समितियों का योगदान बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से हाथ मिलाया है। इसके तहत राज्य के हर गांव तक सहकारी डेयरी का विस्तार किया जाएगा। सहकारी डेयरी क्षेत्र की वित्तीय जरुरतें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) पूरी करेगा। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, 'मध्य प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ लीटर दुग्ध का उत्पादन होता है, जो देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत है। इसमें सहकारी डेयरियों का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। राज्य के कुल दुग्ध उत्पादन में सहकारी डेयरियों की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य का सरपल्स दुग्ध साढ़े तीन करोड़ लीटर है। इनमें से 2.5 प्रतिशत ही सहकारी डेयरी के पास आता है। अभी यहां केवल 17 प्रतिशत गांवों में ही दूध संग्रह की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाने की बहुत जरूरत है।

एनडीडीबी के साथ हाथ मिलाने पर राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के 83 प्रतिशत गांवों तक सहकारी डेयरी के विस्तार की संभावना है।' शहरों में दुग्ध की मांग 1.20 करोड़ लीटर प्रतिदिन है, जिस पर किसान को ठीक से मुनाफा नहीं मिलता। इस अनुबंध के तहत सहकारिता मंत्री ने शुरुआती पांच साल में 50 प्रतिशत गांव में सहकारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति की स्थापना का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। अगर 50 प्रतिशत गांव में सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति स्थापित हो गई तो सहकारी क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग की क्षमता कई गुणा बढ़ जाएगी। इससे किसानों के हाथ में नगदी आएगी और वे समृद्ध होंगे।

श्री शाह ने पशुपालकों की व्यावहारिक दिक्कतों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब किसान अपना दुग्ध खुले बाजार में बेचने जाता है तो उसका शोषण होता है। हमारा लक्ष्य है कि तेजी से हर गांव के किसान को सहकारी डेयरी से जोड़ा जाए। साथ ही, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि दूध से पनीर, दही, छाछ, मट्ठा आदि बनाकर बेचा जाए और मुनाफा किसान को मिले। मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों

डेयरी क्षेत्र की वित्तीय जरुरतें पूरी करेगा एनसीडीसी

में प्राथमिक डेयरी का विस्तार करना है, दूध का कलेक्शन बढ़ाना है। पशुओं को अच्छा चारा उपलब्ध कराना है, उनकी ब्रीड सुधारनी है ताकि हर पशु ज्यादा दूध दे। दुग्ध को प्रोसेस करके ज्यादा मुनाफे के साथ बेचने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है।

सहकारिता मंत्री के अनुसार, गुणवत्ता की जांच और किसानों को हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन को नीति निर्माण और ब्रांडिंग का काम करना होगा। एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ को आक्रमक तरीके से काम करना चाहिए ताकि कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो।

उन्होंने कहा कि किसानों को उसके दूध उत्पादन का शत प्रतिशत फायदा मिलना चाहिए, तभी दूध का उत्पादन बढ़ सकेगा। मोदी सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य के किसानों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। सहकारी क्षेत्र को जीवित करने का यह स्वर्णिम अवसर है। मध्य प्रदेश को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। राज्य में कृषि, पशुपालन और सहकारिता, तीनों

- मध्य प्रदेश के दूध उत्पादन में सहकारी डेयरी समितियों का योगदान बढ़ाने के लिए हुआ अनुबंध
- गांवों में सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति स्थापित होने से बढ़ेगी मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता

क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं।

इनका शत-प्रतिशत दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। अब यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने पैक्स को पुनर्जीवित करने, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाने, शहरी सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की दिशा में प्रयास किए हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहले पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज बनाने का काम किया और राज्य सरकारों को इसे स्वीकृति के लिए

भेजा। सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। इस कदम से सहकारिता क्षेत्र में नई जान आई है। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होती, तब तक तीन स्तरीय सहकारी खाका मजबूत नहीं हो सकता। पहले पैक्स सिर्फ लघु अवधि के कृषि ऋण देने का काम करते थे जिससे उनकी आय कम होती थी। आज पैक्स 20 से अधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नए सुधारों से पैक्स की आय बढ़ रही है।

पैक्स में ही मिल रही हैं हर तरह की सेवाएं

पैक्स को जन औषधि केंद्र, जल वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। आज 300 से ज्यादा योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर लोगों के लिए उपलब्ध हैं। रेल टिकट, बिजली बिल, पानी बिल, जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने के लिए अब किसी को गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह सारी सुविधाएं अब पैक्स में उपलब्ध हैं। पैक्स अब फर्टिलाइजर के डीलर भी बन सकते हैं, पेट्रोल पंप भी शुरू कर सकते हैं, रसोई गैस का वितरण भी कर सकते हैं और 'हर घर नल' योजना का संचालन भी कर सकते हैं।

नए बायलॉज के तहत पैक्स, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों को एक कर बहुद्देशीय पैक्स (एमपैक्स) बनाने का काम हुआ। केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपए खर्च करके देश के सभी पैक्स का कम्प्युटराइजेशन कराया है। पैक्स के कंप्युटराइजेशन में पूरे देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अब जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक कम्प्यूटर नेटवर्क के कारण नाबार्ड से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन ऑडिट की व्यवस्था होने से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता भी आई है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कम्प्युटराइज हो चुके पैक्स 13 भाषाओं में काम कर रहे। केंद्र सरकार ने पैक्स के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराया है कि अगर किसान को बैंक अकाउंट खोलना है, तो मध्य प्रदेश में हिंदी में काम होगा, गुजरात में गुजराती में, बंगाल में बांग्ला में और तमिलनाडु में तमिल में काम होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी समितियों एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल से किसानों को उपज का उचित दाम, निर्यात के लिए प्लेटफार्म मिल रहा और मुनाफा सीधे बैंक खाते में पहुंच रहा है। ■

नौ प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है मध्य प्रदेश

3.5 करोड़ लीटर सरप्लस दुग्ध उत्पादन करता है मध्य प्रदेश

1.20 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन शहरों में का मांग

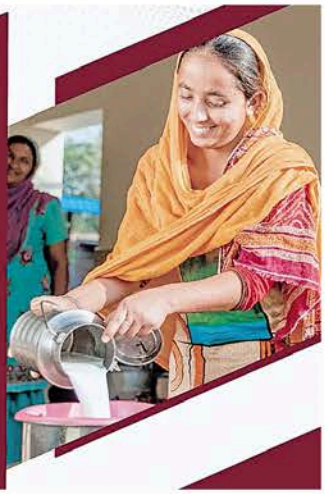

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वांचल के एक लाख पशुपालकों की मेहनत को सराहा

बनास डेयरी से पूर्वांचल के दुग्ध उत्पादकों का बदल रहा जीवन

10 वर्षों में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना

20 हजार से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां चला रही हैं दुग्ध संग्रह केंद्र

100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि बनास डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों को बोनस के रूप में बांटा

सहकार उदय टीम

काशी में हजारों परिवारों के जीवन और नियति को नया आकार देने वाली बनास डेयरी के परिवर्तनकारी प्रभाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बनास डेयरी ने इस क्षेत्र में गिर गायों को वितरित किया है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनारस में पशु आहार की व्यवस्था शुरू करके डेयरी ने कड़ी मेहनत को पुरस्कृत किया है। इससे यहां की डेयरी की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। उन्होंने पूर्वांचल के लगभग एक लाख किसानों से दूध एकत्र करने, उन्हें सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए डेयरी क्षेत्र की सराहना की।

श्री मोदी ने बनास डेयरी प्लांट से जुड़े पशुपालक परिवारों को बोनस के वितरण का जिक्र कर कहा कि 100 करोड़ रुपए से अधिक का यह बोनस कोई उपहार नहीं, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का पुरस्कार है। इन प्रयासों ने पूर्वांचल की कई महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने में सक्षम बनाया है। अब वे आजीविका की चिंताओं से मुक्त होकर समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। यह प्रगति केवल बनारस और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में स्पष्ट है। देश के लाखों किसानों और पशुपालकों के निरंतर प्रयासों से भारत दूध उत्पादन में दुनिया का सिरमौर बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 10 वर्षों में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है।

प्रधानमंत्री ने डेयरी क्षेत्र को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए की गई पहलों की ओर इशारा किया, जिसमें पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाओं से जोड़ना, ऋण सीमा बढ़ाना और सब्सिडी कार्यक्रम का शुभारंभ शामिल है। उन्होंने पशुओं की सुरक्षा के लिए खुरपका-मुंहपका रोग के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि संगठित दूध संग्रह के लिए 20,000 से अधिक सहकारी समितियों को फिर से कार्यान्वित करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें लाखों नए सदस्य दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े हैं।

बनास डेयरी से जुड़े प्रदेश के दूध आपूर्तिकताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वैज्ञानिक प्रजनन के माध्यम से देसी मवेशियों की नस्लों को विकसित करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया। इन पहलों का उद्देश्य पशुपालकों को नए विकास मार्गों, बेहतर बाजारों और अवसरों से जोड़ना है। ■

7/14/25, 4:54 PM Sahkar Uday 26 Issue - Hindi

वाराणसी को विकास योजनाओं की सौगात देकर बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

काशी भारत की विविधता का प्रतिनिधि

3,880
करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की वाराणसी को सौगात

10 वर्षों
में वाराणसी परिक्षेत्र में लगभग
45,000
करोड़ रुपए का निवेश

सहकार उदय टीम

- काशी उनकी और वे भी काशी के : प्रधानमंत्री
- विकास व विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने के विजन का सर्वोत्तम मॉडल बन रही काशी

काशी ने आधुनिकता को अपनाते हुए न सिर्फ अपनी विरासत को संजोया है बल्कि उज्ज्वल भविष्य को भी अपनाया है। भगवान महादेव द्वारा निर्देशित प्राचीन काशी अब प्रगतिशील और पूर्वांचल के आर्थिक मानचित्र का केंद्र भी है। इन विचारों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थानीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3,880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के मौके पर व्यक्त किया। काशी से अपने गहरे जुड़ाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी उनकी है और वे काशी के हैं।

काशी को निरंतर सशक्त बनाने, इसे सुंदर बनाए रखने तथा इसकी प्राचीन भावना को आधुनिक पहचान के साथ जोड़ने की सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी को संरक्षित करने का अर्थ भारत की आत्मा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास को नई गति मिली है। काशी और पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों से जुड़ी कई परियोजनाओं के शुभारंभ का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क को मजबूत बनाने, हर घर में नल से जल पहुंचाने और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल सुविधाओं को विस्तार दिया जा रहा है। इन योजनाओं से काशी के हर निवासी को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने हर क्षेत्र, हर परिवार और हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यह पहल पूर्वांचल को एक विकसित क्षेत्र में बदलने में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होंगी।

काशी में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अपूर्व विकास

विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाने की भारत की यात्रा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने काशी को इस मॉडल का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताया और कहा कि काशी भारत की आत्मा और विविधता का सबसे सुंदर प्रतिनिधि है। काशी के हर मोहल्ले में अनूठी संस्कृति और हर गली में दिखाई देने वाले भारत के अलग-अलग रंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने काशी-तमिल संगमम

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jvzs/ 14/32

काशी बन रही आरोग्य की राजधानी

स्वास्थ्य सेवा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी में न केवल अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि रोगियों का पूरी गरिमा के साथ उपचार हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना को गरीबों के लिए वरदान बताते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी में हजारों और पूरे प्रदेश में लाखों लोगों को इस योजना से लाभ हुआ है। इस योजना ने प्रदेश के लाखों परिवारों के करोड़ों रुपए बचाए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना के शुभारंभ का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह पहल 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करती है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि वाराणसी ने करीब 50 हजार वय वंदना कार्ड जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के साथ अब सरकार लोगों के स्वास्थ्य देखभाल की वित्तीय जिम्मेदारी उठाती है। इस क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी अब आरोग्य की राजधानी बन रही है। श्री मोदी ने कहा कि सुविधाओं को लोगों के करीब लाना ही विकास का सार है। हाल के वर्षों में प्रदेश में अपूर्व विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने न केवल अपने आर्थिक परिदृश्य को बदला है, बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी बदला है। यह प्रदेश अब केवल संभावनाओं की भूमि नहीं है, बल्कि क्षमता और उपलब्धियों की संकल्प भूमि बन गया है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर 'मेड इन इंडिया' की बढ़ती लोकप्रियता पर जोर दिया, जिसमें भारत में बने उत्पाद अब वैश्विक ब्रांड बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी और उसके आसपास के जिलों के 30 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं। यह टैग वस्तुओं की पहचान का पासपोर्ट हैं। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पेंटिंग, ठंडाई, भरवां लाल मिर्च, लाल पेड़ा और तिरंगा बर्फी आदि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। उन्होंने कहा कि जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मूंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठकला और लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी जैसे उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी की खुशबू अब सीमाओं को पार कर रही है और अपनी विरासत को दूर-दूर तक फैला रही है।

> जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं व पीलीभीत की बांसुरी को मिला जीआई टैग

जैसी पहलों पर प्रसन्नता जताई और कहा कि ऐसे पहल एकता के सूत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने काशी में आगामी एकता मॉल की घोषणा की, जो एक छत के नीचे भारत की विविधता को प्रदर्शित करेगा और देश भर के विभिन्न जिलों के उत्पाद प्रस्तुत करेगा।

अपने कार्यकाल में काशी के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र कर श्री मोदी ने कहा कि काशी की सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डे आदि के विकास की आगंतुकों ने व्यापक प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग प्रतिदिन बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं और पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। पहले छोटे-छोटे त्योहारों के दौरान होने

वाले ट्रैफिक जाम और यात्रियों को धूल व गर्मी की असुविधाओं को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि फुलवरिया फ्लाईओवर के निर्माण और अन्य विकास कार्यों से दूरियां कम हुई हैं और समय की बचत के साथ ही दैनिक जीवन में आसानी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रिंग रोड बनने से घंटों तक लगने वाली भीड़भाड़ खत्म हो गई है और जौनपुर व गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के साथ-साथ बलिया व मऊ जिले के लोगों को भी हवाई अड्डे तक की यात्रा काफी कम समय में सुलभ हुई है। उन्होंने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 10 वर्षों के दौरान करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का जिक्र कर कहा कि क्षेत्र में बेहतर यातायात संपर्क और चौड़ी सड़कों के निर्माण से गाजीपुर, जौनपुर, मिजार्पुर व आजमगढ़ जैसे शहरों में यात्रा तेज और सुविधाजनक हो गई है। इससे क्षेत्रीय विकास की गति मिली है। श्री मोदी ने कहा कि निवेश ने न केवल बुनियादी ढांचे को बल्कि विश्वास को भी बदल दिया है, जिससे काशी और पड़ोसी जिलों को लाभ हुआ है।

लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के वर्तमान में जारी विस्तार और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हवाई अड्डे के पास छह लेन की भूमिगत सुरंग के निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भदोही, गाजीपुर और जौनपुर को जोड़ने वाली परियोजनाएं शुरू हुई है। भिखारीपुर व मंडुआडीह में काफी दिनों से लंबित फ्लाईओवर निर्माण का हुआ है। श्री मोदी ने बनारस शहर और सारनाथ को जोड़ने वाले एक नए सेतु के निर्माण की घोषणा की, जिससे अन्य जिलों से सारनाथ जाने वाले यात्रियों को शहर से होकर गुजरने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में इन परियोजनाओं के पूरा होते ही बनारस में आवागमन और भी सुविधाजनक हो जाएगा। इस प्रगति से क्षेत्र में गति और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने काशी में सिटी रोपवे के ट्रायल की शुरूआत का भी जिक्र किया और कहा कि इससे बनारस ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि बनारस में होने वाला हर विकास और बुनियादी ढांचा परियोजना पूर्वांचल के युवाओं को लाभ देता है। उन्होंने युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए बनारस में नए स्टेडियमों के निर्माण और युवा एथलीटों के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं के विकास के साथ-साथ एक नए खेल परिसर के उद्घाटन का जिक्र किया, जहां वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों को इन मैदानों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है।■

राजस्थान के कोटपुतली में सनातन सम्मेलन में बोले श्री अमित शाह

सामाजिक समरसता व सांस्कृतिक जागरण के संकल्प को पूरा कर रही मोदी सरकार

एक वर्ष
से चल रहे
108
कुण्डीय रुद्र महा मृत्युंजय महायज्ञ के माध्यम से बाबा नस्तीनाथ ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का महान कार्य किया

सहकार उदय टीम

देश में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरण बढ़ाने का जो संकल्प बाबा बालनाथ महाराज ने लिया था, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारें पूरा कर रही हैं। इस तथ्य को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राजस्थान के कोटपुतली जिले के पावटा में 108 कुण्डीय रुद्र महा मृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णाहुति एवं सनातन सम्मेलन के दौरान दोहराया। बाबा बालनाथ महाराज की समाधि का दर्शन कर श्री शाह ने कहा कि तप, तपस्या और त्याग से भरा उनका जीवन सभी को मार्गदर्शित करता रहेगा। बाबा बालनाथ की प्रेरणा से इस आश्रम में 16 वर्षों से लगातार यज्ञ का आयोजन बाबा नस्तीनाथ कर रहे हैं और उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़कर यहां एक वर्ष पहले 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू किया था, जिसमें इस वर्ष रामनवमी तक समाज के हर हिस्से से लोगों ने पवित्र भाव के साथ शामिल हुए हैं और प्रकृति के संरक्षण, सनातन के प्रचार और आत्मा की शुद्धि के लिए यज्ञ किया है। श्री शाह ने कहा कि समाज को जोड़ने, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने और पर्यावरण की सेवा करने का ऐसा प्रयास उन्होंने अबतक नहीं देखा है। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशामुक्ति की प्रतिज्ञा की और सामाजिक समरसता के प्रतीक बने। उन्होंने कहा कि इस अखंड धूनि को एक महासिद्ध योगी ने शुरू किया और बाबा नस्तीनाथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। महाप्रभु आदिनाथ से लेकर नौ गुरुओं और उनके बाद ऊर्जा के अनेक वाहकों के माध्यम से नाथ संप्रदाय ने सनातन धर्म को शक्ति प्रदान किया है। नाथ संप्रदाय में धूनि को पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के पंच तत्वों को मिलाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम माना गया है।

भारत में अनेक संत, महापुरुष और ऋषि-मुनि रहे हैं और बाबा बालनाथ भी ऐसे एक महायोगी थे जिन्होंने यहां जन्म लेकर देश-विदेश में 84 धूनियों की स्थापना की और अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाया। मानव योनि के 84 चक्रों से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, तब यह स्थान उनके तप से बेहद ऊर्जावान हो गया। यहां अनेक हताश मन और जीवन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा लोगों को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया के माध्यम से जीवन आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बाबा बालनाथ के सत्य और तपस्या में विश्वास रखने, वैराग्य व सेवा को जीवन का आधार बनाने, प्राकृतिक जीवन जीने और पशु-पक्षियों की सेवा करने के सिद्धांतों को बाबा नस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गुरु की तरह ही लोकधर्म, लोककल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए अनेक प्रकार के प्रकल्पों को दिशा दे रहे हैं।■

मुंबई में गुजराती साहित्यिक कार्यक्रम में बोले श्री अमित शाह

देश के निर्माण में गुजराती साहित्य के पत्र-पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

सहकार उदय टीम

- देश की आजादी के बाद 'चित्रलेखा' ने समाज की समस्याओं एवं साहित्य दोनों को बहुत ही सटीक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया

साहित्य समाज की जरूरत है और यह समाज के समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। देश के निर्माण में गुजराती साहित्य के पत्र-पत्रिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुजराती साप्ताहिक 'चित्रलेखा' के 75वें स्थापना दिवस समारोह में साझा किया। श्री शाह ने कहा कि 'चित्रलेखा' की यह यात्रा गुजरात के साहित्य, समाज, जीवन, गुजरात और देश व समाज की समस्याओं का प्रतिबिंब रही है। देश की आजादी के बाद वर्ष 1950 में 'चित्रलेखा' शुरू हुई और समाज की समस्याओं एवं साहित्य दोनों को बहुत ही सटीकता से लोगों के समक्ष रखने का कार्य किया। 'चित्रलेखा' में प्रकाशित होने वाले उपन्यासों के माध्यम से समाज को एकजुट

75 वर्ष की यात्रा गुजरात के साहित्य, समाज, जीवन, गुजरात और देश की समस्याओं का प्रतिबिंब

गुजराती साहित्य परिषद ने 1855 में 'बुद्धि प्रकाश' नामक एक पत्रिका शुरू की थी। उस समय सभी ने रिवाज के विरुद्ध मोर्चा शुरू करने का कार्य 'बुद्धि प्रकाश' की प्रेरणा से किया। वर्ष 1876 में नानालाल ने 'सत्य विहार' शुरू कर समाज में अद्भुत जागरूकता फैलाई। महात्मा गांधी ने 1919 में 'नवजीवन' शुरू किया और सत्य को कटु से कटु स्वरूप में लोगों को परोसने का काम किया।

रखने का सफल प्रयास हुआ, जिससे गुजराती पढ़ने वाले युवाओं को अध्ययन की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि 'चित्रलेखा' ने पाठकों से जिस तरह जुड़ाव बनाए रखा है, वह बहुत कम देखने को मिलता है। यह तभी मुमकिन होता है जब मुनाफे का विचार नहीं हो और उद्देश्य की पवित्रता, साहित्य के प्रति समर्पण एवं समाज की समस्या का निराकरण करने का मन हो। श्री शाह ने कहा कि एक जागृत साप्ताहिक हमारे समाज और जीवन पर अनेक प्रकार से गहरा प्रभाव डालता है। अंग्रेजी बोलने के जमाने में जब गुजराती साहित्य को जिंदा रखना कठिन था, तब वजूभाई ने 'चित्रलेखा' की स्थापना की।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात के अनामत आंदोलन के समय समाज बिखर रहा था, लेकिन उस समय 'चित्रलेखा' ने समाज को एक सूत्र में पिरोये रखने की मशाल अपने हाथों में ली। 75 वर्षों के तथ्य पूर्ण प्रयासों के कारण ही 'चित्रलेखा' की विश्वसनीयता बनी। उन्होंने कहा कि जब से पढ़ना सीखा, तब से 'चित्रलेखा' देखता हूं। कभी हरकिशन मेहता का उपन्यास, तो कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कभी पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले कार्टून को पढ़ते-देखते

26/11
आतंकवादी हमले का सटीक और सत्य निरूपण किसी ने
'चित्रलेखा'
की तरह नहीं किया होगा

हुए कब समाज के प्रश्नों को पढ़ने और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करने की वृत्ति होने लगी, यह पता ही नहीं चला। श्री शाह ने कहा कि आज निर्भीक रूप से समाज की सभी समस्याओं का निरूपण करने और समस्या के प्रति सवाल ही नहीं, उसके निराकरण के लिए सुझाव देने की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि अब तक अपने जीवन में तीन घर बदले हैं, किंतु 'चित्रलेखा' तीनों घरों में निरंतर आता रहा।

'चित्रलेखा' ने अनेक ऐसे विशेषांक दिए जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। उसके नर्मदा योजना विशेषांक ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया था। मुंबई पर हुए 26/11 आतंकवादी हमले का सटीक और सत्य निरूपण किसी ने 'चित्रलेखा' की तरह नहीं किया होगा। उसने आतंकवाद की समस्या को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाई। 'चित्रलेखा' ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी तीन विशेषांक प्रकाशित किए। श्री शाह ने कहा कि वे बचपन से राम मंदिर के समर्थक रहे हैं, उसके लिए लड़े और जेल भी गए, किंतु 'चित्रलेखा' की तरह किसी ने इस मुद्दे का निरूपण नहीं किया। उन्होंने कहा कि नगीन दास, तारक मेहता और गुणवंत शाह 'चित्रलेखा' के प्लेटफार्म से लोकप्रिय बने और राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ■

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोले प्रधानमंत्री

भारत ने एकाधिकार नहीं, मानवता को प्राथमिकता दी

सहकार उदय टीम

- भारत 21वीं सदी के लिए समावेशी व सहभागी वैश्विक व्यवस्था की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा है
- भारत न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है, बल्कि भविष्य को आकार देने और सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है

दुनिया की दृष्टि भारत पर है और सभी भारत को लेकर जिज्ञासा से भरे हुए हैं। दुनिया भारत को देख रही है और यह समझने के लिए उत्सुक है कि आज भारत क्या सोचता है। वैश्विक समुदाय अब भारत के विचारों, नवाचारों और प्रयासों को पहले से कहीं अधिक महत्व देता है। राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाले इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में साझा किया। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ शुरूआत है, क्योंकि वैश्विक मंचों पर भारत की क्षमताएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।' पिछले 10-11 वर्षों में भारत में सभी क्षेत्रों में हुए व्यापक बदलावों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने मानसिकता में हुए महत्वपूर्ण बदलावों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक भारत में एक ऐसी मनोदशा को बढ़ावा दिया गया, जो विदेशी सामान को बेहतर मानती थी। उन दिनों व्यवसायी अक्सर विदेशी वस्तुओं का बखान कर कहते थे कि यह आयात की हुई वस्तु है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अब यह स्थिति बदल गई है और आज लोग सक्रिय रूप से पूछते हैं, 'क्या यह भारत में बना (मेड इन इंडिया) है?' उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है, बल्कि भविष्य को आकार देने और सुरक्षित करने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 21वीं सदी के लिए वैश्विक संस्थाओं की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई है। हमने एकाधिकार नहीं, बल्कि मानवता को हमेशा प्राथमिकता दी है तथा समावेशी व सहभागी वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रयास किया है। इससे सामूहिक योगदान और सहयोग सुनिश्चित हुआ है।

दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती का समाधान करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के साथ भारत ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना की पहल की। भारत ने पुलों, सड़कों, भवनों और बिजली ग्रिडों सहित आपदारोधी अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे छोटे देशों के लिए भी स्थायी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समाधान के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की पहल की है और 100 से अधिक देश इस पहल में शामिल हो चुके हैं। यह प्रयास न केवल जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों की ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। ■

नई विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत हुई

वैश्विक व्यवस्थाओं को अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक बनाने के भारत के प्रयासों से जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। श्री मोदी ने वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में वैश्विक दक्षिण देशों की आवाज के रूप में भारत की भूमिका का जिक्र किया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए वैश्विक व्यवस्था के विकास समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन प्रयासों से नई विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया और कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन विकसित किए और देश में तेजी से टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को दवाइयों की आपूर्ति की। वैश्विक संकट के समय में भारत के सेवा और करुणा के मूल्य दुनिया भर में गूंजे और इसकी संस्कृति एवं परंपराओं का सार प्रदर्शित हुआ।

श्री अमित शाह ने कठुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किया संवाद

पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवान आधुनिक तकनीक से होंगे लैस

सहकार उदय टीम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर यात्रा के दौरान कठुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट 'विनय' पर वहां तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के साथ संवाद किया। जवानों के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि यहां आकर पता चलता है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश या फिर 45 डिग्री तापमान हो, इतनी भीषण भौगोलिक और मौसम की विषमता के बावजूद जवान तत्परता के साथ और चौकस रहकर सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री शाह ने जम्मू क्षेत्र की अंतराष्ट्रीय सीमा की निगरानी के प्रयासों के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों की सराहना की।

देश की सुरक्षा में बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूरा देश जानता है कि बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है। सीमा सुरक्षा बल ने इस दायित्व का हमेशा बहुत अच्छे से निर्वहन किया है। पाकिस्तान के साथ हुई हर जंग में भारतीय सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनाती के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम के दो मॉडल बने हैं। पूरी सीमा पर इनकी तैनाती के बाद जवानों को सूचना प्राप्त करने और दुश्मन द्वारा किसी भी हरकत की स्थिति में तत्काल जवाब देने के लिए तकनीक के माध्यम से बहुत सहजता हो जाएगी। सीमा पर घुसपैठ को चिन्हित करने और सुरंग को तकनीक के माध्यम से ढूंढने और नष्ट करने के लिए भी कई प्रयोग हुए हैं।

- केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित
- सीमा पर तैनात जवानों की ड्यूटी में आने वाली तकलीफें होंगी कम

श्री शाह ने कहा कि कुछ ही वर्षों में पूरी भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सुरक्षाबल के जवान आधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। हमारे जवानों का त्याग, वीरता, बलिदान और हौसला सीमापार दुश्मन से भारत को हमेशा बचाते हैं। और इसी कारण देश की जनता के दिलों में बीएसएफ के प्रति सम्मान का भाव है। सीमाओं पर तकनीक से संबंधित 26 से अधिक पहल के परीक्षण किए जा रहे हैं। इनमें ड्रोनरोधी तकनीक, टनल आइडेंटिफिकेशन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसे पहलू शामिल हैं।

श्री शाह ने वर्ष 2019 में कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल के शहीद सहायक समादेष्टा, विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की और सीमा पर नवनिर्मित 8 महिला बैरक, हाई मास्ट लाइटस, जी 1 टॉवर और कम्पोजिट बीओपी का लोकार्पण किया। इनके निर्माण की लागत 47.22 करोड़ रुपए आई थी। सरकार की इस पहल से सीमा सुरक्षा बल कर्मियों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। सीमाओं की कठिन परिस्थितियों मे उनके रहन सहन की सुविधाएं भी बेहतर हो गई हैं।

केन्द्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। भारत सरकार ने सुरक्षाबलों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिनमें आयुष्मान, सीएपीएफ, अनुग्रह भुगतान, सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज, यूनिफाइड पेंशन योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना और ई-आवास शामिल हैं।■

मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम में आयोजित समारोह में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नया भारत 'विकास के साथ विरासत' के मंत्र से कर रहा तेज प्रगति

- 'राम वन गमन पथ' में मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा
- चंदेरी साड़ियों को मिला जीआईटैग
- प्राणपुर में शिल्प हथकरघा पर्यटन गांव की स्थापना

सहकार उदय टीम

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम का दौरा किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पुष्टि की और इसे प्राप्त करने का विश्वास जताते हुए भारत की प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि कई देशों ने विकास की खोज में अपनी परंपराओं से संपर्क खो दिया है। श्री मोदी ने कहा, ''भारत की संस्कृति न केवल इसकी पहचान से जुड़ी है, बल्कि इसकी क्षमताओं को मजबूत करती है।'' उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र द्वारा निर्देशित गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार के संकल्प को दोहराते हुए जोर देकर कहा कि ''सेवा की यह भावना सरकार की नीति और प्रतिबद्धता दोनों है।''

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा की भावना व्यक्तियों को समाज, राष्ट्र और मानवता के बड़े उद्देश्यों से जोड़ती है। उन्होंने सेवा में लगे लोगों के समर्पण को स्वीकार किया और इस बात का जिक्र किया कि कैसे निस्वार्थ सेवा के कार्यों के माध्यम से कठिनाइयों पर विजय पाना हमारा स्वभाव बन जाता है। श्री मोदी ने सेवा को एक आध्यात्मिक अभ्यास बताया और इसकी तुलना पवित्र गंगा से की, जिसमें सभी को डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आनंदपुर धाम ट्रस्ट की सराहना की और विश्वास जताया कि ट्रस्ट की सेवा संबंधी पहल विकसित भारत के विजन में नई ऊर्जा का संचार करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अशोक नगर और आनंदपुर धाम जैसे क्षेत्रों ने राष्ट्र के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कला, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की समृद्ध विरासत की ओर संकेत करते हुए विकास और विरासत की उनकी विशाल क्षमता का जिक्र किया और मध्य प्रदेश और अशोक नगर में प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी जिक्र किया। इनमें चंदेरी साड़ियों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के माध्यम

आनंदपुर धाम में 315 हेक्टेयर में 500 से ज्यादा गायों वाली एक आधुनिक गौशाला

से चंदेरी हथकरघा को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्राणपुर में एक शिल्प हथकरघा पर्यटन गांव की स्थापना शामिल है। ■

सेवा भावना ही सरकार की कल्याणकारी पहलों का मूल

श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा की गई हर पहल के मूल में सेवा की भावना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर जरूरतमंद व्यक्ति भोजन की चिंता से मुक्त है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा की चिंता से मुक्त किया है, जबकि पीएम आवास योजना वंचितों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित कर रही है। जल जीवन मिशन गांवों में पानी की समस्या का समाधान कर रहा है और रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना से गरीब से गरीब बच्चे भी अपने सपने साकार कर रहे हैं। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसके तहत देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। श्री मोदी ने "राम वन गमन पथ" के विकास कार्यों पर देते हुए कहा कि इस पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा और प्रदेश की उल्लेखनीय और अनूठी पहचान से परिचित कराते हुए इसकी विशिष्टता को और मजबूत करेंगी।

आनंदपुर की पवित्र भूमि में परोपकार की परंपरा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुरु जी महाराज मंदिर में दर्शन-पूजन किया और आनंदपुर धाम में मंदिर का दर्शन करके खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संतों की तपस्या से पोषित इस पवित्र भूमि में परोपकार एक परंपरा बन गई है। यहां सेवा का संकल्प मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने प्रथम पादशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और अन्य पादशाही संतों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारा भारत ऋषियों, मनीषियों और संतों की धरती है, जिन्होंने हमेशा चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समाज का मार्गदर्शन किया है।'' उन्होंने उस युग को याद किया जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहन ज्ञान की व्याख्या की थी। श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक काल के दौरान समाज ने इस ज्ञान से अपना संपर्क खोना शुरू किया था। लेकिन, पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने अद्वैत के ज्ञान को आम लोगों के लिए सुलभ और सरल बनाकर इस विरासत को आगे बढ़ाया। भौतिक प्रगति के बीच युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों के क्षरण की दबावपूर्ण वैश्विक चिंताओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा, ''इन मुद्दों का समाधान अद्वैत के दर्शन में निहित है।'' उन्होंने परमहंस दयाल महाराज को उद्धृत किया, जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत को सरल शब्दों में कहा कि 'आप जो हैं, मैं वही हूं।' ''मेरा और तुम्हारा'' के विभाजन को समाप्त करने वाले इस विचार को सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाए, तो यह सभी संघर्षों को हल कर सकता है। श्री मोदी ने आनंदपुर धाम में स्थापित ध्यान के पांच सिद्धांतों का जिक्र किया, जिसमें निःस्वार्थ सेवा को बताया गया है। वंचितों की सेवा की भावना और मानवता की सेवा के कार्य में नारायण को देखना भारतीय संस्कृति का आधार है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर किया कि आनंदपुर ट्रस्ट समर्पण के साथ सेवा की इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है।

भारतीय संस्कृति की राजदूत बनकर ब्रह्माकुमारी संस्था विश्व में दे रही शांति का संदेश

सहकार उदय टीम

- ब्रह्माकुमारी संस्था ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा किया
- विश्व में योग, ध्यान और आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे करोड़ों लोग; आने वाले समय में यह विश्व शांति का मार्ग बनेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम 2047 में आजादी की शताब्दी के समय विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारी परंपराओं में विश्व बंधुत्व की ओर ले जाने की क्षमता, हर मानव के अंदर की आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने और हर जीवन को सदवृति के मार्ग पर चलाने की शक्ति है और भारत की ब्रह्माकुमारी जैसी संस्थाएं इस दिशा में अच्छे से काम कर रही हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को राजस्थान में सुरक्षाबल कर्मियों के लिए 'आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म-सशक्तिकरण' विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किया। श्री शाह ने कहा कि हमारे सुरक्षाबलों के त्याग, तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। हमारे सुरक्षाबल हर प्रकार के कठिन वातावरण और परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्यों के पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा में कानून और व्यवस्था को संभालकर निर्बल लोगों को संरक्षण देते हैं। इस काम में होने वाले तनाव से सुरक्षाकर्मियों को बाहर लाने में ब्रह्माकुमारी संस्था की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों

से सुरक्षाबलों के बीच जाकर उनके तनाव को कम करने और शांत मन व स्वस्थ शरीर के साथ देश की सुरक्षा को और अच्छे से सुनिश्चित करने की दिशा में उनका यह प्रयास प्रशंसनीय हैं।

श्री शाह ने ब्रह्माकुमारी संस्था की 'विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान' का लोकार्पण भी किया और कहा कि संस्था ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनियाभर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा किया है। योग और ध्यान के माध्यम से ब्रह्माकुमारी पूरे विश्व में शांति व साधना का दीप प्रज्ज्वलित कर रहे हैं और हर व्यक्ति के अंदर की सद्वृत्ति को जागृत करने के उनके प्रयास से एक अद्भुत शांति का वातावरण निर्मित हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन, शाकाहार, नशामुक्ति, सादगीपूर्ण जीवन, ध्यान और इसके माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति से शुद्ध, शांत और अमर आत्मा के अंश की अनुभूति करने जैसी सारी चीजों को ब्रह्माकुमारी ने सरल व सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। ब्रह्माकुमारी मातृशक्ति के माध्यम से पूरे विश्व में शांति और संवाद का संदेश लेकर भारत की संस्कृति के राजदूत बनकर काम कर रहे हैं। ■

25 वर्षों
से सुरक्षाकर्मियों के तनाव को कम करने के ब्रह्माकुमारीज के प्रयास प्रशंसनीय हैं

21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने से पूरे विश्व में पहुंची वैदिक परंपरा

श्री शाह ने कहा कि योग और आध्यात्म से मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा को एकरूप कर ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर जाने और चिंतन से समस्याओं के निवारण के लिए नीतियों का सृजन करना भारत की पुरानी परंपरा रही है। हम इस परंपरा को आज भी पूरे विश्व में पहुंचे के लिए प्रयासरत हैं। भारत ने सबसे पहले 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना विश्व को दी और हमारे उपनिषदों ने पूरे विश्व को हमारा परिवार बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने २१ जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर हमारी वैदिक परंपरा को पूरे विश्व तक पहुंचाया। इससे अब विश्व में करोड़ों लोग अपने जीवन को योग, ध्यान और आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ा रहे हैं। यह रास्ता ही आने वाले दिनों में विश्व शांति का रास्ता बनेगा।

हरियाणा के हिसार में बोले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

'हवाई चप्पल वालों का हवाई जहाज में यात्रा करने का सपना पूरा'

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देशवासियों को सुरक्षित और किफायती हवाई यात्रा सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। इस योजना पर 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री मोदी ने हरियाणा के लोगों की ताकत, खेल भावना और भाईचारे को राज्य की पहचान बताते हुए अपने इस वादे को एक बार फिर

- प्रधानमंत्री ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला, 410 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा
- वर्ष 2014 तक देश में थे 74 हवाई अड्डे, इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई
- उड़ान योजना के तहत लगभग 90 हवाई अड्डों को जोड़ा गया

दोहराया कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ेंगे और कहा कि वह सपना अब पूरे देश में साकार हो रहा है। गुरु जम्भेश्वर, महाराजा अग्रसेन और पवित्र अग्रोहा धाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने विकसित हरियाणा और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और खेल एवं कृषि के क्षेत्र में राज्य के वैश्विक प्रभाव की प्रशंसा की।

600
से अधिक मार्गों पर देशवासियों के लिए सस्ती हवाई यात्रा सुलभ

श्री मोदी ने जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में लाखों भारतीयों ने पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव किया है। इस दौरान देश के उन क्षेत्रों में भी नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं जहां पहले उचित रेलवे स्टेशन भी नहीं थे। जहां आजादी के बाद के 70 वर्षों में भारत में 74 हवाई अड्डे ही थे, आज इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है। उड़ान योजना के तहत लगभग 90 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है। इससे 600 से अधिक मार्गों पर देशवासियों के लिए सस्ती हवाई यात्रा सुलभ हो गई है और इससे सालाना हवाई यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। विभिन्न एयरलाइनों ने 2,000 नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिससे पायलटों, एयर होस्टेस और अन्य सेवाओं के लिए हजारों नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही, विमान रखरखाव क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, ''हिसार हवाई अड्डा हरियाणा के युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाएगा तथा उन्हें नए अवसर और सपने प्रदान करेगा।'' ■

गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय पर सरकार का जोर

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से विकसित भारत के निर्माण में बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारी सरकार गरीबों के कल्याण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रही है। उन्होंने दुःख जताते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी, केवल 16 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल का पानी का कनेक्शन था, जिसका अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में उनकी सरकार ने 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे कवरेज 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक पहुंच गया है। वंचित वर्गों के लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया है। उनकी सरकार के दौरान खुले जन धन खातों के सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से हैं।

सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की समीक्षा बैठक

सहकारी समितियों की होगी ऑनलाइन ऑडिटिंग

सहकार उदय टीम

- 'मेरी समिति मेरा पटल' पोर्टल लॉन्च, सहकारी समितियों की चुनौतियों का समाधान करने में होगा मददगार

सहकारी समितियों को पारदर्शी, प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उनके डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके माध्यम से सहकारी संस्थाओं के कामकाज को न सिर्फ डिजिटली सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि यह प्रयास भी किया जा रहा है कि जल्द ही उनकी ऑडिटिंग भी ऑनलाइन होने लगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में हरियाणा में सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण और विस्तार की प्रगति पर समीक्षा बैठक की जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, उन्होंने 'मेरी समिति मेरा पटल' नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल सहकारी समितियों की चुनौतियों का समाधान करने में मददगार होगा।

समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के समक्ष आने वाली समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए ठोस योजनाओं के साथ उन्हें आदर्श संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। राज्य सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि को इन बैंकों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाना चाहिए और किसानों को 85 प्रतिशत तक ऋण गारंटी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 2,500 नए पैक्स खोलने के लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (आरआईसीएम) में 'विकसित भारत का निमार्णः सहकारिता, किसान सशक्तिकरण और विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, प्रभावशाली और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सम्मेलन में श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा रहा है। सहकारी समितियों को एकीकृत और मजबूत करने के लिए स्टैंडर्ड बायलॉज विकसित किए जा रहे हैं और पैक्स की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए उनका कम्प्युटरीकरण किया जा रहा है। पैक्स को मल्टी फंक्शनल बनाने के लिए उसे 25 प्रकार की सेवाएं देने की मंजूरी दी गई है। इससे उसके सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अधिक अवसर खुलेंगे, जिससे समुदायों और राष्ट्र को लाभ होगा।

श्री गुर्जर ने कहा कि अगले पांच साल में पंजाब में 9,000 और हरियाणा में 2,500 नई सहकारी समितियां बनाई जाएंगी जिससे इस क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, किसानों की आजीविका को मजबूत करना और सहकारिता के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना था। ■

पशुपालन बन रहा ग्रामीण समृद्धि का आधार: भूटानी

- सहकारिता समीक्षा बैठक में देशभर में सहकारी क्षेत्र को और मजबूत एवं आधुनिक बनाने के लिए पहल और रणनीति तैयार करने पर की गई चर्चा

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ''सहकार से समृद्धि'' के विजन को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारी क्षेत्र को नई ऊर्जा और स्पष्ट रणनीतिक दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसका मकसद सहकारी क्षेत्र को और मजबूत एवं आधुनिक बनाना है। इसी कड़ी में केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में मेघालय की राजधानी शिलांग में दो दिवसीय (10-11 अप्रैल, 2025) राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. भूटानी ने देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र की सटीक भागीदारी को आंकने के लिए सभी सहकारी समितियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) एकत्र करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय मजबूत अंतर राज्यीय सहयोग के साथ सहकारी नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल पारदर्शिता, विश्लेषण और नीति निर्धारण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पशुपालन को ग्रामीणों की समृद्धि बढ़ाने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि कि पशुपालन अब पारंपरिक खेती से कहीं ज्यादा आर्थिक संभावनाओं वाला क्षेत्र बन चुका है। डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 शुरू किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और बाल पोषण को बढ़ावा मिल रहा है। असम, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी की जा रही है। आजादी के बाद देश में पहली बार बन रहे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी को लेकर डॉ. भूटानी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है। यह विश्वविद्यालय सभी राज्यों में सहकारी शिक्षा को मानकीकृत करेगा और 250 से अधिक मौजूदा सहकारी संस्थाओं का उत्थान करेगा।

समीक्षा बैठक में देशभर में सहकारी क्षेत्र को और मजबूत बनाने और आधुनिक बनाने के लिए पहल और रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, सहकारी संघों के अधिकारी, वित्तीय संस्थानों और नीति निमार्ताओं सहित प्रमुख हितधारक शामिल हुए। राज्यों की समीक्षा सत्र में सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल), भारतीय बीज सहकारी संघ लिमिटेड (बीबीएसएसएल), एनसीसीएफ और नैफेड जैसे राष्ट्रीय सहकारी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

दो दिवसीय सत्रों में मुख्य रूप से सहकारी समितियों के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और माइक्रो-एटीएम के माध्यम से घर-घर बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करना, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शून्य ब्याज ऋण का प्रावधान और ग्रामीण सहकारी बैंकिंग को मजबूत करना शामिल था। साथ ही, बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी समितियों (एमपैक्स), पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों, अनाज भंडारण योजना और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के डिजिटलाइजेशन को समय पर पूरा करने पर चर्चा हुई ताकि उनकी पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और सेवा पहुंच में सुधार हो सके।

इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक समर्पित कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें सहकारी समितियों के लिए बेंचमार्किंग, प्रभाव मूल्यांकन और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना तैयार करने जैसी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडलों ने सहकारी विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा किया। ■

विशेष आलेख

संदीप कुमार नायक

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटेंगी सहकारी संस्थाएं

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर सहकारी संस्थाएं तैयार हैं। विश्व भर में इसे लेकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जी-20 देशों की भूमिका अहम है। वर्ष 2030 तक निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और नेट जीरो वर्ष 2050 को प्राप्त करने के लिए देश की कोऑपरेटिव संस्थाओं की पूरी तैयारी है। सीसीए (कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट चेंज) का गठन इस संदर्भ में एक सार्थक पहल है। जी 20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे पर लगभग सभी देशों की गहरी चिंता है। इसे लेकर विश्व के ज्यादातर देशों की सहकारी समितियां इस दिशा में सक्रिय हैं।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) के सम्मेलन में डेढ़ सौ अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इसी तरह जी 20 सदस्य देशों की हैसियत धरती की दो तिहाई जनसंख्या के बराबर है। वैश्विक जीडीपी का इसकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। जबकि सदस्य देश विश्व व्यापार के 75 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं का सालाना टर्नओवर 2,146 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। विश्व भर में करीब 30 लाख सहकारी समितियां हैं। इनमें भारत की अकेले हिस्सेदारी लगभग साढ़े आठ लाख है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एलआईएफई (लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ऐम) का आह्वान किया। सहकारी समितियां और उनके सदस्य लाइफ से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या का एक बड़ा तबका कृषि और उससे जुड़े कार्यों से अपनी आजीविका चलाता है। अधिकांश किसान सहकारी समितियों से जुड़े हैं, उदाहरण के लिए 94 प्रतिशत किसान किसी न किसी सहकारी समिति के सदस्य हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका और अधिक हो जाती है।

बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का मुख्यालय है। आईसीए में जी-20 देशों की बड़ी संख्या में सहकारी समितियां हैं। जी-20 में आईसीए की भी भागीदारी बढ़नी चाहिए, हालांकि भारत में इफको, जीसीएमएमएफ (अमूल) और कृभको जैसे विश्व के बड़े सहकारी संगठन हैं। यह सभी सहकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए जी-20 सम्मेलन में 'वसुधैव कुटुंबकम्' को मुख्य थीम रखा गया, जिसका आशय है एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य। इसी साल जून महीने में फ्रांस में आयोजित की गई पेरिस समिट फॉर ए न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, जुलाई महीने में यूनाइटेड नेशन का उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम, सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर आयोजित एसडीजी शिखर सम्मेलन तथा दिसंबर में दुबई में सीओपी 20 और भविष्य के 2024 शिखर सम्मेलन की संभावित अगुवाई तथा भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी 20 के आदि आयोजन सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियां महत्वपूर्ण हैं।

सहकार के सात प्रमुख सिद्धांतों में समुदाय को अहम रूप से शामिल किया जाता है, अंतारराष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंकिंग सेवाओं में सुधार करने के लिए त्वरित निर्णय लेने की जरूरत है, जिससे सहकारी समितियां निम्न कार्बन वर्ल्ड के लिए तेजी से अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। जी 20 सम्मेलन मे 'जी 20 ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट' पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जी 20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि वर्ष 2030 तक एसडीजी या सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रमुख चुनौतियां हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली गतिविधियां जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, जैव विविधता हानि और भूमि उत्पादकता क्षति को रोका जाए। इफको नैनो यूरिया का इस संदर्भ में सराहनीय योगदान है। जैसा कि जी 20 समूह देशों ने जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में कारगर उपाय अधिक प्रभावकारी हो सकते हैं। कृषि सहकारी समितियां और उनके सदस्यों को इसके लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देश जैसे अफ्रीका, आइसलैंड और तटीय देशों की सरकारों के साथ मिलकर कोऑपरेटिव में साझेदारी की जा सकती है। यूनाइटेड नेशन एजेंसी और जी 20 ग्रीन फाइनेंस के माध्यम से सहकार बैंकिंग सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीएम) को अपने सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, आने वाले वर्षों में जी 20 के साथ अपनी भागीदारी का विस्तार करना चाहिए। ■

(पूर्व एमडी, एनसीडीसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)

चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स का अवलोकन करते केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर। सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे संगठनों और स्वयं सहायता समूहों ने इन स्टॉल्स पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के मैगलगंज में स्थित आईएफएफडीसी के बीज प्रसंस्करण इकाई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी। इस अवसर पर इफको के निदेशक मंडल के सदस्यों की भी उपस्थिति रही।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सहकारी बंधुओं के साथ सहकारिता वार्तालाप कार्यक्रम में इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी का स्वागत करते वरिष्ठ सहकारी बंधु श्री कोशल शर्मा। साथ हैं इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार (दाएं)। इस दौरान डॉ. अवस्थी ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करने के लिए सहकारी बंधुओं को प्रोत्साहित किया।

श्वेत क्रांति 2.0 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग एनडीडीबी द्वारा संयुक्त रूप से उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव अलका उपाध्याय ने की।

वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सहकारी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए मुंगेर-जमुई केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के तहत एमपैक्स और एम-डीसीएस के सदस्यों के लिए नया खाता खोलने को प्रोत्साहित करने के मेगा अभियान में बिहार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार सदस्यों को बैंकिंग किट वितरित करते हुए।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों की स्विगी के प्लेटफॉर्म पर बिक्री हेतु समझौता हुआ। स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ श्री अमितेश झा और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री डी के वर्मा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

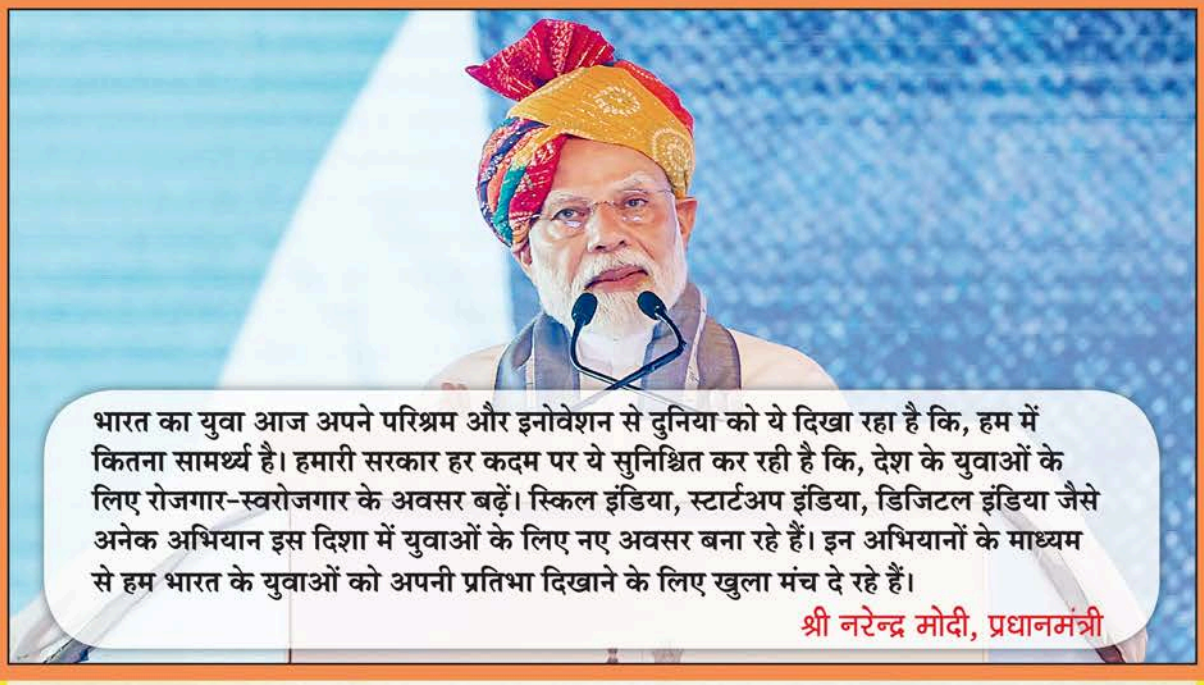

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
NANO UREA PLUS
सागरिका SAGARIKA
NANO DAP
IFFCO
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें

Published on 26th May 2025
" Sahkar Uday"
RNI No. DLHIN/24/A0001
Postal Registration No.: DL(S)-17/3560/2024-26
Posting Date : 26th - 31st May 2025
Posted at : Lodhi Road HO, New Delhi - 110003